

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2582

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
व्यापारिक निर्यात में गिरावट

2582. श्री बलवंत बसवंत वानखड़े:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को किये जाने वाले व्यापारिक निर्यात में गिरावट के कारण निर्यातकों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ख) यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता की स्थिति क्या है;
- (ग) क्या सरकार डंपिंग रोकने के लिए चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क में संशोधन करने की योजना बना रही है; और
- (घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): यूरोपीय संघ को पण्यवस्तु निर्यात पिछले पाँच वर्षों में बढ़ रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 41.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसी प्रकार, अमेरिका को पण्यवस्तु निर्यात भी पिछले पाँच वर्षों में बढ़ रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में 51.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 86.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ख): भारत ने दिनांक 24 जुलाई 2025 को ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईपीए) के नेगोशिएशन्स के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूरोपीय संघ जून 2022 से एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर नेगोशिएटिंग कर रहे हैं, और नेगोशिएशन्स के बारह दौर पूरे हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम जुलाई 2025 में हुआ था।

(ग) और (घ): व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) घरेलू उद्योग की डंपिंग और क्षति हुई या नहीं यह निर्धारित करने के लिए जाँच करता है। अपनी जाँच के आधार पर, डीजीटीआर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के संबंध में अपने अंतिम निष्कर्ष और सिफारिश वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुपालन में, सामान्य आयात शुल्क एमएफएन के आधार पर लागू किए जाते हैं।
